



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

16/1
28/10/2001

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 726]
No. 726]नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 3, 2001/आश्विन 11, 1923
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 3, 2001/ASVINA 11, 1923

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 2001

का० आ० 986(अ).—यतः नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (अब से इन्हें एनोएलोएफोटी० के रूप में जाना जाए) का स्पष्ट लक्ष्य अन्य सशस्त्र अलगाववादी संगठनों के सहयोग और सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से त्रिपुरा को भारत से अलग करके स्वतंत्र "बोरोक्लैण्ड त्विपरा" की स्थापना करना तथा अलगाव के लिए त्रिपुरा के स्थानीय लोगों को भड़काना है, जिससे त्रिपुरा को भारत से अलग किया जा सके।

और यतः ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (जिसे इसके पश्चात ए०टी०टी०एफ० कहा गया है) का स्पष्ट लक्ष्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य सशस्त्र अलगाववादी संगठनों के सहयोग से, त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, मेघालय तथा अरुणाचल प्रदेश को शामिल करके सात प्रदेशों के एक पृथक राष्ट्र की स्थापना करना, जिससे उक्त राज्य भारत से अलग हो सकें तथा इन राज्यों को भारत संघ से अलग करने के लिए सशस्त्र संघर्ष को जारी रखना है और इस प्रकार इन राज्यों को भारत से अलग करना है।

और यतः केन्द्र सरकार का मत है कि एनोएलोएफोटी० और ए०टी०टी०एफ० :

- (I) अपने लक्ष्य के अनुसरण में विद्रोही तथा हिंसक गतिविधियों में लिप्त हैं एवं इस प्रकार इन्होंने सरकार के प्राधिकार को क्षति पहुंचाई है तथा लोगों में डर व आतंक फैलाया है,
- (II) नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड (एनोएस०सी०एन०) (आई०एम०) के इसके स्व गुट, दि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) तथा मणिपुर के भैतई उग्रवादी संगठनों जैसे अन्य विधि विरुद्ध संगठनों के साथ संपर्क बनाए हैं जिसका लक्ष्य उनका समर्थन हासिल करना है,

- (III) हाल के पिछले कुछ समय में अपने उद्देश्य एवं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई हिंसक तथा विधि विरुद्ध गतिविधियों में लिप्त रहे हैं जो कि भारत की प्रभुसत्ता तथा एकता के लिए द्वानिकर हैं।

और यतः केन्द्रीय सरकार का यह भी मत है कि हिंसक एवं विधि विरुद्ध गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

- (क) नागरिकों तथा पुलिस एवं सुरक्षा बलों के कार्मिकों की हत्या,
- (ख) त्रिपुरा में व्यवसायियों एवं व्यापारियों सहित जनता से जबरन धन ऐंठना,
- (ग) असामाजिक एवं अवैध माध्यमों से भारी मात्रा में परिष्कृत शस्त्र व गोलाबारूद जुटाना तथा उन्हें गुप्त रूप से पड़ोसी देश के माध्यम से भारत में लाना,
- (घ) सुरक्षित आश्रय, प्रशिक्षण, शस्त्र व गोलाबारूद आदि जुटाने के प्रयोजन के लिए पड़ोसी देश में शिविर स्थापित करना तथा उन्हें बनाए रखना,
- (ङ) त्रिपुरा में जनजातीय एवं गैर जनजातीय समुदायों के बीच साम्राज्यिक संघर्ष उत्पन्न करने एवं उनमें वृद्धि करने के लिए अन्य त्रिपुरा जनजातीय संगठनों के साथ संबंध स्थापित करना और उन्हें बनाए रखना।

और यतः केन्द्र सरकार का मत है कि एन०एल०एफ०टी० और ए०टी०टी०एफ० की उपरोक्त गतिविधियां भारत की प्रभुसत्ता एवं अखण्डता विरोधी हैं तथा ये विधि विरुद्ध संगम हैं,

अतः अब विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एन०एल०एफ०टी०) और दि ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ए०टी०टी०एफ०) को एक विधि विरुद्ध संगम घोषित करती है।

और यतः केन्द्र सरकार का यह भी मत है कि यदि इन पर तत्काल नियंत्रण न किया गया तो एन०एल०एफ०टी० और ए०टी०टी०एफ० को अवसर मिलेगा कि वे :-

- (I) अपने काडर की अलगाववादी, विद्रोही, आतंकवादी/ हिंसक गतिविधियां बढ़ाएंगे,
- (II) भारत की प्रभुसत्ता एवं राष्ट्रीय अखण्डता के विरुद्ध शक्तियों के साथ सहयोग करके राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का प्रचार करेंगे,
- (III) नागरिकों तथा पुलिस व सुरक्षा बलों के कार्मिकों की हत्याओं में वृद्धि में लिप्त हो जाएंगे,
- (IV) अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार से और अधिक गैर कानूनी हथियार एवं गोलाबारूद प्राप्त करने तथा जुटाने में लिप्त हो जाएंगे,
- (V) गतिविधियों के लिए जनता से बड़ी राशि इकट्ठा करने तथा जबरन धन ऐंठने में लिप्त हो जाएंगे।

और यतः उपरोक्त परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में केन्द्र सरकार की पक्की राय है कि एन०एल०एफ०टी० और ए०टी०टी०एफ० को तत्काल प्रभाव से एक विधि विरुद्ध संगम घोषित करना आवश्यक है, और

तदनुसार उक्त खण्ड-3 की उपधारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एवं द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत किए जाने वाले किसी भी अध्यादेश के अध्यधीन, यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

[फाइल सं० 9/8/2001-एन.इ. I]

सुरेन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2001

S. O. 986(E).— Whereas the National Liberation Front of Tripura (hereinafter referred to as the NLFT) has its professed aim, to establish an independent “Borokland Twipra” by liberation of Tripura from India through armed struggle in alliance with other armed secessionist organisations of Tripura and incite indigenous people of Tripura, for secession and thereby the secession of Tripura from India;

And whereas the All Tripura Tiger Force (hereinafter referred to as the ATTF) has its professed aim, the formation of a separate nation of seven sisters comprising Tripura, Assam, Manipur, Mizoram, Nagaland, Meghalaya and Arunachal Pradesh resulting in bringing about the secession of the said States from India, in alliance with other armed secessionist organisations of the North East region and to carry on armed struggle for separation of these States from India and thereby secession of these States from India;

And whereas, the Central Government is of the opinion that the NLFT and the ATTF have, -

- (I) been engaging in subversive and violent activities, thereby undermining the authority of the Government and spreading terror and violence among the people for achieving its objective;
- (ii) established linkages with other unlawful associations, viz., the Isak Swu faction of National Socialist Council of Nagaland [NSCN(I/M)], the United Liberation Front of Assam (ULFA) and Meitei extremist outfits of Manipur with the aim of mobilising their support;
- (iii) In pursuance of its aim and objective in the recent past, engaged in several violent and unlawful activities which are prejudicial to the sovereignty and integrity of India;

And whereas, the Central Government is also of the opinion that their violent and unlawful activities include, -

- (a) killing of civilians and personnel belonging to the Police and Security Forces;
- (b) extortion of funds from the public including businessmen and traders in Tripura;

- (c) procuring large number of arms and ammunitions, including sophisticated ones, through clandestine or illegal channels and inducting them secretly into Tripura through a neighbouring country;
- (d) establishing and maintaining camps in a neighbouring country for the purpose of safe sanctuary, training procurement of arms and ammunitions, etc.
- (e) establishing and maintaining linkages with other Tripura tribal extremist groups for causing and fomenting communal clashes between the tribal and non-tribal communities in Tripura;

And whereas the Central Government is of the opinion that the aforesaid activities of the NLFT and the ATTF are detrimental to the sovereignty and integrity of India and that they are unlawful associations;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the National Liberation Front of Tripura (NLFT) and the All Tripura Tiger Force (ATTF) as unlawful associations;

And whereas the Central Government is also of the opinion that if there is no immediate curb and control, the NLFT and the ATTF will take the opportunity to,-

- (i) mobilise their cadres for escalating their secessionist, subversive, terrorist and violent activities;
- (ii) propagate anti-national activities in collusion with forces inimical to India's sovereignty and national integrity;
- (iii) indulge in increased killings of civilians and targeting of the Police and Security Forces personnel;
- (iv) procure and induct more illegal arms and ammunitions from across the International border;
- (v) extort and collect huge funds from the public for their activities.

And whereas, the Central Government, having regard to the above circumstances, is of the firm opinion that it is necessary to declare the NLFT and the ATTF as unlawful associations with immediate effect; and accordingly in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of the said section 3, the Central Government hereby directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[File No. 9/8/2001-NE. I]

SURENDRA KUMAR, Jt. Secy.